

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 21, शुक्रवार, शाके 1944-फरवरी 10, 2023 Magha 21, Friday, Saka 1944- February 10, 2023	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2023

संख्या: एफ.13(03)विशा/विस/2023/ :-राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 जैसा कि दिनांक
10 फरवरी, 2023 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ
प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

2023 का विधेयक सं. 3

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम
बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2023 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम
कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4 के उपबंध
उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 59 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह मास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 33. पट्टा- जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार या इनका कोई भी नवीकरण है,- खण्ड (i) से (vi) में उल्लिखित लिखतों की दशा में सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर निम्नलिखित कारकों को पट्टे की कालावधि पर लागू करने से अभिप्राप्त टेलीस्कोपिक दर पर, अर्थात्:-

जहां ऐसा पट्टा-

- | | |
|--|-------|
| (i) एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 0.02; |
| (ii) एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 0.12; |
| (iii) पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए | 0.9; |

तात्पर्यित है

- (iv) दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है 2;
- (v) पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है 5;
- (vi) बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है 8;
- (vii) तीस वर्ष से अधिक की कालावधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है, वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है:

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूट.- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।

स्पष्टीकरण.- पट्टे की कालावधि अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष से कम की कोई कालावधि अगले एक वर्ष में पूर्णांकित की जायेगी।

दृष्टांत.-

1. पांच वर्ष के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-

$$[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12)] = 0.5 = 0.1$$

5

5

2. पन्द्रह वर्ष और पांच मास के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर
अभिप्राप्त करना:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (1 \times 5)]}{16} = \frac{20}{16} = 1.25$$

3. पच्चीस वर्ष के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त
करना:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (5 \times 5) + (5 \times 8)]}{25} = \frac{80}{25} = 3.2 \text{ |"}|$$

उद्देश्यों और कारणों का कथन
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 59 का खण्ड (i) परिसीमा की कालावधि को दो मास से छह मास तक बढ़ाये जाने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि इसे उक्त धारा के खण्ड (ii) और (iii) के अधीन विहित परिसीमा की कालावधियों के समरूप किया जा सके।

पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की दरों के साथ ही संगणना का तरीका युक्तिसंगत किये जाने की दृष्टि से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय

राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(5)वित्त/कर/2023 दिनांक 10.02.2023]

प्रेषक:श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 3 of 2023

*(Authorised English Version)***THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2023**

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2023-24.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2023.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clause 4 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

3. Amendment of section 59, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In clause (i) of section 59 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "two months", the expression "six months" shall be substituted.

4. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act, for the existing Article 33, the following shall be substituted, namely:-

- " **33. Lease-** Including an under lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal thereof,- In case of instruments mentioned in clauses (i) to (vi) on the market value of the property at the telescopic rate obtained by applying the following factors on the period of lease, namely:-

Where such lease purports to be-

(i) for a period not exceeding one year	0.02;
(ii) for a period exceeding one year but not exceeding five years	0.12;
(iii) for a period exceeding five years but not exceeding ten years	0.9;
(iv) for a period exceeding ten years but not exceeding fifteen years	2;
(v) for a period exceeding fifteen years but not exceeding twenty years	5;
(vi) for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years	8;
(vii) for a period exceeding thirty years or in perpetuity, or which does not purport for any definite period	The same duty as on a conveyance (No.21) on the market value of the property:

Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed hundred rupees.

Exemption.- Lease executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink).

Explanation.- For the purpose of determining the period of a lease any period less than one year shall be rounded off to the next one year.

Illustrations.-

1. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 5 years:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12)]}{5} = \frac{0.5}{5} = 0.1$$

2. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 15 years and 5 months:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (1 \times 5)]}{16} = \frac{20}{16} = 1.25$$

3. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 25 years:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (5 \times 5) + (5 \times 8)]}{25} = \frac{80}{25} = 3.2 \text{ "}$$

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

Clause (i) of section 59 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to extend the limitation period from two months to six months so as to make it similar to limitation periods prescribed under clause (ii) and (iii) of the said section.

With a view to rationalize the rates as well as method of calculation of stamp duty on the lease deed, Article 33 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**अशोक गहलोत,
Minister Incharge.**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय**राज्यपाल महोदय की सिफारिश****[सं.प. 12(5)वित्त/कर/2023 दिनांक 10.02.2023]****प्रेषक:श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2023-24.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,

Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.